भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2255

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है ।

21 फाल्गुन, 1946 (शक)

डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए आईटी कंपनियों के साथ सहयोग

2255.श्री यदुवीर वाडियार :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत राज्यवार, विशेषकर कर्नाटक में, कुल कितने लाभार्थी हैं;

(ख) मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों में एआई और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कोई नए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो मैसूर में स्वीकृत नए केंद्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) डिजिटल साक्षरता और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए आईटी कंपनियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) कर्नाटक राज्य सहित राष्ट्रव्यापी स्तर पर 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) में डिजिटल साक्षरता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। 6 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में, देश भर में लगभग 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। पीएमजीदिशा योजना आधिकारिक तौर पर 31 मार्च, 2024 को संपन्न हुई थी।

कर्नाटक राज्य में, इस योजना के तहत कुल 17,072 प्रशिक्षण केंद्र पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से 765 मैसूरु से थे, जिसमें पीएमजीदिशा योजना के तहत राज्य भर में कुल 29,64,726 उम्मीदवार नामांकित थे और 24,40,957 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।

पीएमजीदिशा योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): कौशल विकास कार्यक्रमों में एआई और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. **साइबर सुरक्षित भारत**- सरकार की साइबर सुरक्षित भारत पहल सरकारी संगठनों और छोटे व्यवसायों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिये निःशुल्क साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी डिजिटल संपत्ति सुरक्षित करने में मदद मिलती है। सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) परियोजना के तहत विषयगत क्षेत्रों में से एक में एआई-संचालित खतरे का पता लगाने, स्वचालन और साइबर रक्षा रणनीतियों में क्षमता निर्माण शामिल है, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा में अत्याधुनिक कौशल के साथ हितधारकों को लैस करना है।

ii. **फ्यूचरस्किल्स प्राइम**- एमईआईटीवाई ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के साथ संयुक्त रूप से "फ्यूचरस्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नई / उभरती प्रौद्योगिकियों, अर्थात् ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, एडिटिव

मैन्युफैक्चरिंग/3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल और साइबर सुरक्षामें उम्मीदवारों को फिर से री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग करना है।

iii. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट)** पेशेवरों और छात्रों को गहन ज्ञान से लैस करने के लिए डिज़ाइन किए गए एनएसक्यूएफ-संरेखित पाठ्यक्रमों की पेशकश करके अपने कौशल विकास कार्यक्रमों में एआई और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण को सक्रिय रूप से एकीकृत कर रहा है। ये पाठ्यक्रम मूलभूत एआई अनुप्रयोगों से लेकर विशेष साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तक हैं, जो विभिन्न कौशल स्तरों और अवधियों को शामिल करती हैं। मानकीकृत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, नाइलिट साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, नाइलिट ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से अग्रणी आईटी कंपनियों के साथ कार्यनीतिक सहयोग भी स्थापित किया है। इन साझेदारियों का उद्देश्य छात्रों को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से लैस करना, विकसित डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल साक्षरता और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

iv. **युवाआई– एआईके साथ उन्नति और विकास के लिए युवा**: राष्ट्रीय ई-शासनप्रभाग(एनईजीडी), एमईआईटीवाईने अपने सहयोगियों के सहयोग से, " **युवाआई– एआईके साथ उन्नति और विकास के लिए युवा**" लॉन्च किया है- स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका उद्देश्य कक्षा 8 से 12 वीं तक के स्कूली छात्रों को एआईतकनीक और सामाजिक कौशल के साथ समावेशी तरीके से सक्षम बनाना है। यह कार्यक्रम युवाओं को 8 विषयगत क्षेत्रों- कृषि, आरोग्य, शिक्षा, पर्यावरण, परिवार, ग्रामीण विकास, स्मार्ट सिटीज और विधि और न्याय में एआई कौशल सीखने और लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

(ग): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को लागू कर रहा है, जो अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान करने के लिए देश भर के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षासहित उद्योग से संबंधित कौशल से लैस करके रोजगार के अवसरों तक पहुंचने के लिए युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से है। दिनांक 31.12.2024 तक, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत 19,715 उम्मीदवारों को एआई/साइबर सुरक्षा से संबंधित रोजगार की भूमिकाओं में प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

इसके अलावा, एमएसडीई के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के माध्यम से एआई-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक पाठ्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (एआईपीए) शुरू किया है। उद्योग और अकादमिक विशेषज्ञों के सहयोग से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सभी सीटीएस प्रशिक्षुओं के लिए 7.5 घंटे का एक माइक्रो-क्रेडेंशियल पाठ्यक्रम "इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)" विकसित किया गया है।

(घ): एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कौशल वृद्धि के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से देश के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, रोजगार के अवसर और उद्यमिता सहायता प्रदान करता है। एसआईडीएच एआई और एमएल पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें 'फंडामेंटल्स ऑफ एज़ोर एआई स्पीच' और 'मशीन लर्निंग' जैसे मूलभूत कार्यक्रमों से लेकर 'गूगल क्लाउड जनरेटिव एआई' और 'एआई स्ट्रैटेजी टू क्रिएट बिजनेस वैल्यू इन हेल्थकेयर' जैसी विशेष पेशकशें शामिल हैं, जो विशेषज्ञता और एप्लिकेशन के विभिन्न स्तरों को पूरा करते हुए, प्रतिभागियों को एआई और एमएल तकनीक में सबसे आगे रहने में सक्षम बनाता है।

******

अनुबंध- I

पीएमजीदिशा योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार हासिल की गई उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत उम्मीदवार	प्रशिक्षित उम्मीदवार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,564	2,931
2	आंध्र प्रदेश	23,01,731	19,17,452
3	अरुणाचल प्रदेश	14,949	11,615
4	असम	27,21,585	23,60,195
5	बिहार	82,40,606	74,12,740
6	छत्तीसगढ़	24,86,455	21,37,064
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	20,522	18,029
8	गोवा	58,569	53,784
9	गुजरात	30,31,310	26,83,286
10	हरियाणा	18,57,815	15,77,109
11	हिमाचल प्रदेश	6,61,922	5,32,976
12	जम्मू और कश्मीर	8,70,451	7,06,991
13	झारखंड	27,52,731	22,86,356
14	**कर्नाटक**	**29,64,726**	**24,40,957**
15	केरल	1,77,165	1,18,132
16	लद्दाख	24,785	22,122
17	लक्षद्वीप	142	35
18	मध्य प्रदेश	56,92,467	50,69,449
19	महाराष्ट्र	61,23,970	53,23,817
20	मणिपुर	28,397	18,286
21	मेघालय	1,52,783	1,06,063
22	मिजोरम	30,317	23,125
23	नागालैंड	11,990	8,968
24	ओडिशा	36,16,441	30,86,143
25	पुडुचेरी	22,079	15,801
26	पंजाब	17,46,448	15,14,820
27	राजस्थान	45,06,184	39,70,690
28	सिक्किम	27,035	23,122
29	तमिलनाडु	17,04,537	14,07,880
30	तेलंगाना	14,56,226	12,10,448
31	त्रिपुरा	3,25,000	2,64,186
32	उत्तर प्रदेश	1,63,14,369	1,45,48,273
33	उत्तराखंड	7,85,978	6,73,306
34	पश्चिम बंगाल	28,36,714	23,95,565
कुल		**7,35,71,963**	**6,39,41,716**

***चंडीगढ़ और दिल्ली शहरी संकुल में हैं, इसलिए योजनाके अंतर्गत शामिल नहीं हैं।**

****